भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4130
दिनांक 19 दिसंबर, 2024

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन

†4130. डॉ. राजकुमार सांगवान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की नीति और कार्य-योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गैस एजेंसी विपणन योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य के किन-किन स्थानों पर गैस एजेंसियां स्थापित नहीं की गई हैं/खोली नहीं गई हैं;

(ग) उक्त गैस एजेंसियों को कब तक स्थापित किए जाने/खोले जाने की संभावना है;

(घ) किन-किन स्थानों पर गैस आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(ड.) उक्त क्षेत्रों में किस दर पर एलपीजी की आपूर्ति/वितरण किया जा रहा है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ड.): पूरे देश में गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त, 2021 में (उज्ज्वला 2.0) की शुरूआत की गई थी, जिसे जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। इसके साथ ही सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत और 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निश्चय किया तथा दिसंबर 2022 के दौरान उज्ज्वला 2.0 के 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लक्ष्य को पहले ही हासिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को अनुमोदित कर दिया था जिसे

पहले ही जुलाई, 2024 में हासिल किया जा चुका है। दिनांक 01.12.2024 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 10.33 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थी हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरुप देश में अप्रैल 2016 में एलपीजी कवरेज 62% से अब संतृप्ति के निकट है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की शुरुआत करना एक सतत प्रक्रिया है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के लिए एकीकृत चयन दिशानिर्देश 2016 के तहत स्थापना करने, के लिए स्थलों की पहचान की जाती है और विज्ञापित की जाती हैं। दिनांक 01.12.2024 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के पास ग्रामीण क्षेत्रों के 3138 डिस्ट्रीब्यूटरों सहित 4145 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं ।

एकीकृत चयन दिशानिर्देश 2016 के तहत विज्ञापित स्थलों के एक हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 16 स्थलों को विपणन योजना में शामिल किया गया था तथा अप्रैल 21 से विज्ञापित किया जा रहा है। दिनांक 01.12.2024 की स्थिति के अनुसार इनमे से 11 को पहले ही कमीशन किया जा चूका है तथा 5 कमीशनिंग के विभिन्न चरणों में हैं। एलपीजी आपूर्ति तथा एलपीजी मूल्यों के निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए इन स्थलों के नाम, वर्तमान स्थिति, वैकल्पिक व्यवस्था **अनुलग्नक** में दी गयी है।

सरकार घरेलू एलपीजी के मूल्यों को घटाती-बढ़ाती रहती है तथा देश में घरेलू एलपीजी को किफायिती बनाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। इस दिशा में सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए दिनांक 30 अगस्त, 2023 से घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य में प्रति 14.2 कि.ग्रा. एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की कमी की है। इसके अलावा, सरकार ने दिनांक 9 मार्च, 2024 से घरेलू एलपीजी के आरएसपी में 100 रुपए प्रति 14.2 कि. ग्रा.सिलेंडर की और कमी की है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी का वर्तमान आरएसपी 803/-रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर है।

दिनांक 21 मई, 2022, से सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए एक वर्ष में अधिकतम 12 रिफिलों तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा, सरकार ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 से प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के सभी लाभार्थियों के लिए निर्धारित राजसहायता बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर कर दी है।300 रुपए प्रति सिलेंडर (और 5 किलोग्राम सिलिंडर के लिए समानुपातिक रूप से आनुपातिक) की निर्धारित राजसहायता के साथ वर्तमान में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी लागत 503 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर (दिल्ली में) है।

अनुलग्नक

''उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन'' के संबंध में डॉ. राजकुमार सांगवान द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4130 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	स्थल	जिला	स्थिति	गैस आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था
1	मिर्जापुर	मिर्जापुर	फिर से ड्रा होना बाकी है	हां
2	पैतेपुर	सीतापुर	फिर से ड्रा होना बाकी है	हां
3	लखनऊ नगर सीमा के भीतर वार्ड सं. 2 (राजा बिजली पासी द्वितीय), वार्ड सं. 03 (राजा बिजली पासी प्रथम)	लखनऊ	फिर से ड्रा होना बाकी है	हां
4	अहिरौली बघेल	देवरिया	एलओआई जारी कर दिया गया है	हां
5	थिरिया निजावत खान	बरेली	एलओआई जारी कर दिया गया है	हां

स्रोत :उद्योग के आधार पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

****